शीर्षक से छपी खबर की ओर दिलाना चाहूंगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अखबार में छपी खबर सच है ?

सभापति जी, खबर के मुताबिक उत्तरांचल के बाराहोती इलाके के 378 वर्ग किलोमीटर तथा लद्दाख की ट्रेक जोन एवं थाकुंग चौकियों वाले क्षेत्रों पर चीन की नजर 1967 से ही थी, परन्तु तब उसने इसे अपने नक्शे में दर्शाया नहीं था, लेकिन वह घुसपैठ की कोशिश जरूर करता रहा है। परन्तु चीनी सैंनिकों ने 1985 से अपनी घुसपैठ बढ़ानी शुरू कर दी । 1998 में चीनी सैनिकों ने इन क्षेत्रों में 77 बार तथा 1999 में 111 बार, वर्ष 2000 में 137 बार, 2001 में 102 बार तथा जून 2002 में 44 बार घुसपैठ की है । सैन्य रिकार्डो के अनुसार भी ऐसी घुसपैठ की घटनाओं को शिल- शिलेवार एंव सुनियोजित सत्य माना गया है ।

सबसे गम्भीर और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब चीन ने इन क्षेत्रों को भारत के नक्शे में मानने से इन्कार कर दिया है । पिछले दिनों दोनों देशों की सीमाओं के संबंध में हुई बैठक में भारत की ओर से दिए गए नक्शे को लेने एवं उसे मानने से इन्कार कर दिया है ।

चूंकि भारतीय सीमा के ये क्षेत्र दुर्गम एवं उबड़-खाबड़ एवं ऊंचाई पर होने तथा चीन की कब्जे वाली भारतीय जमीन के समानान्तर समतल होने से उसकी सेनाओं की घुसपैठ में सहयोगी प्रदान होती है जिसके कारण चीनी सेनायें इन इलाकों में सहजता से घुसपैठ करने में कामयाब हैं ।

सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि उत्तरांचल का बाराहोती इलाका एवं ट्रेक जोन इलाका आज कारगिल जैसी स्थिति में बदल गया है और चीन ने अब उस पर अपना कब्जा एवं अपना अधिकार भी दर्शाना एवं बताना शुरु कर दिया है ।

सभापति जी, मामले की गम्भीरता के मद्देनजर मैं चाहूंगा कि सरकार सदन में इस संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ अपना वक्तव्य दे । सरकार यह भी बताये कि द्वारा चीन के साथ सीमाओं के संबंध में अब तक हुई वार्त्ताओं में क्या इस प्रकार का मुद्दा चीन सरकार द्वारा लाया गया? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या यह भी सच है कि भारत सरकार चीन सरकार के समक्ष अपने पक्ष को रखने में लाचार एवं लचर स्थिति में रही है?? तथा भविष्य में चीन के साथ होने वाली वार्ताओं में इस तरह के उठाये जा रहे मुद्दों का विरोध करेगी?क्या केन्द्र सरकार या विदेश के मंत्रालय द्वारा अब तक चीन द्वारा अपनायी गयी इस तरह की गतिविधियों के प्रति चीन सरकार के समक्ष विरोध एवं इसके गम्भीर परिंणामों के प्रति आगाह किया है और इस पर अपना ऐतराज जाहिर किया है? धन्यवाद।

Screening Test of Students Passing out from Recognised Foreign institutions by Medical Council of India.

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश): **धन्यवाद सभापति महोदय,मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग 2000 विद्यार्थी जो रूस तथा सी.आई.एस.देशों से भारतीय मैडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों से डिग्री लेकर आए हैं , वे धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि 13 फरवरी 2002 को जारी रेगुलेशन से इन विद्यार्थीयों को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। इन विद्यार्थीयों के अभिभावक बहुत सारे पैसे इनकी शिक्षा पर खर्च कर चुके हैं । ये छात्र मैडिकल डिग्री के साथ एक साल इन्टर्नशिप भी कर चुके हैं और उनको पुन: टैस्ट**

देना पड़ रहा है। इस रेगुलेशन से वे डाक्टर भी प्रभावित हुए हैं जो पहले इन्टर्नशिप कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये विधार्थी वह हैं जो मैडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त मैडिकल कालेजों से डिग्री लेकर आए हैं और जो वहां से एक वर्ष की इन्टर्नशिप भी कर चुके हैं। सबसे लज्जा की बात यह हैं कि इनको इन्टर्नशिप हेतु कोई पैसा भी नहीं दिया जाता हैं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं है कि यह रेगुलेशन राज्य सभा के पटल पर लाया भी गया है या नहीं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह 13 फरवरी के मैडिकल रेगुलेशन को वापिस लें और इन छात्रों तथा देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यदि रेगुलेशन लागू ही करना है तो जो छात्र 13 फरवरी 2002 के बाद विदेश पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं, उन छात्रों पर लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Need for Revision of Royalty on Minerals

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir, the State of Orissa is endowed with vast mineral deposits, like coal, iron-ore, manganese ore, bauxite, chromite, limestone, china clay and precious and semi-precious stones, copper, vanadium, etc.

The rate of exploitation/royalty of different minerals is much below the potential. The abundant mineral deposits does not contribute much to the State's revenue, because the royalty on these minerals is not fixed at the expected levels.

Both, the Sarkaria Commission and the Eleventh Finance Commission, have recommended the revision of royalty. In view of the bad economic scenario and resource position of the State of Orissa, I urge upon the Central Government to extend a helping hand in accelerating the growth of economy and in reducing poverty. Thank you.

SHRI BIRABHADRA SINGH (Orissa): Sir, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member, Ms. Pramila Bohidar.

Need For Revival Of Handloom And Textile Industry In Tamil Nadu

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): The handloom and textile industries in Tamil Nadu are in a very bad state of affairs. The latest blow has come due to the removal of exemption duty on hank yarn with effect from 1.3.2002. The total excise duty comes to 9.2 per cent on the ex-mill price.

To boost up the handloom and textile industries, the Tamil Nadu Government has proposed to set up two projects, that is, one at